

हाईवे चैनल

□ वर्ष- 28 □ अंक- 345 □ रावपुर, शुक्रवार 9 जनवरी 2026 □ पृष्ठ- 8 □ मूल्य- 2.50 रुपये □ रावपुर • जगलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू, राबड़ी मीसा भारती, तेजस्वी यादव पर आरोप तय

नई दिल्ली, 9 जनवरी (न्यूज चैनल)। जमीन के बदले नौकरी से जुड़े कथित घोटाले के मामले में दिल्ली की राजस्व एजेंसी कोर्ट ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती, बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था।

विशेष न्यायाधीश विहाल गोपाल ने अपने एक का मत इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया।



कोर्ट से लालू यादव के परिवार को बड़ा झटका

हासिल की। अदालत ने इस मामले में 41 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए और 52 लोगों को बरी कर दिया, जिनमें रेल अधिकारी भी शामिल थे। सीबीआई की चार्जशीट में नामित 103 आरोपियों में से पांच की मृत्यु हो चुकी है। अधिकार अजब अहमद ने कहा, सीबीआई अदालत ने लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, तेजस्वी यादव, तेज प्रकाश यादव और हेमा यादव के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 120बी और 13 के तहत आरोप तय किए हैं। आरोप 29 जनवरी को तय किए जाएंगे।

यादव परिवार ने रेल अधिकारियों और अपने करीबी सहयोगियों को मिलीभगत से जमीन

आरोप तय किए हैं। आरोप 29 जनवरी को तय किए जाएंगे।

सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया फरमान

तबादले वाली जगह पर 13 तक ज्वाइन नहीं किया तो होगी कार्रवाई

रायपुर, 9 जनवरी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों के सचिवों को पत्र लिखकर 13 जनवरी 2026 तक सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने का आदेश दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई भी कर्मचारी या अधिकारी समय सीमा तक जॉइनिंग नहीं करता है, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।



जिलों में संचालित जनहित योजनाओं और सेवाओं पर पड़ रहा है। इस कारण सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को नई पदोस्थापना पर समय पर जॉइनिंग देनी अनिवार्य होगी। निर्देश में कहा गया है कि ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जो स्थानांतरण के बाद अभी तक कार्यभार ग्रहण नहीं कर चुके हैं, उन्हें तत्काल रूप से कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि कोई निर्देशों का अनिवार्य रूप से कार्यभार ग्रहण करेगा, तो उसके खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

ब्रेकिंग न्यूज

जस्टिस दीपक कुमार तिवारी आज हंगे रिटायर

बिलासपुर, 9 जनवरी (हाईवे चैनल)। हाईकोर्ट में 31 जुलाई, 2023 को स्थायी जज के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस दीपक कुमार तिवारी आज रिटायर हंगे। शुक्रवार को सेवा अवधि पूरी होने पर विदाई समारोह आयोजित की जाएगी। दोपहर 3.30 बजे चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम-1 में कार्यक्रम रखा गया है। बता दें कि वह अक्टूबर 2021 में हाईकोर्ट के एडिजिटल जज बने थे।

राहुल गांधी का भाजपा पर तीव्र हमला, कहा-लोगों की जिंदगी की तबाही; लगाए सिलसिलेवार आरोप

नई दिल्ली, 9 जनवरी (न्यूज चैनल)। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमलावर हैं। एक दिन पहले जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टूट के टारिफ को लेकर कड़ा निशाना साधा था। वहीं अब उन्होंने एक लंबे-चुंबे टूट, एकसम के जरिए भाजपा शासित राज्यों पर सिलसिलेवार हमला किया है। कांग्रेस सांसद ने शुक्रवार को अपने बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि देशभर में भ्रष्ट जनता पाटी की डबल इंजन सरकारों ने जनता की जिंदगी तबाह कर दी है। राहुल गांधी के साथ सत्ता का दुरुपयोग और अंधकार का जहर भाजपा की राजनीति में ऊपर से नीचे तक फैल चुका है। राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा, इनके सिस्टम में गरीब, असहाय, मजदूर और मध्यमवर्गीय की जिंदगी सिर्फ अंधकार है और विधायक के नाम पर वसूली-वैच चल रहा है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की निर्मम हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया - लेकिन सवाल की मोदी वही हैं सत्ता का संरक्षण भाजपा के किस वीआईपी की कला रहा है? कांग्रेस सबके लिए बराबर कह होगा।

हिमालय में बजपा चुनावी बिगुल 30 अप्रैल से पहले पंचायत चुनाव कारन के आदेश जारी

नई दिल्ली, 9 जनवरी (न्यूज चैनल)। हिमालय प्रदेश की मुख्य सरकार को 'हिनार कर' की रणनीति पर हाईकोर्ट ने विचार लग दिया है। पंचायत चुनावों को आगे धक्काने की सरकार की योजना को बड़ा झटका देते हुए, अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि गांव की सरकार चुनने में अब और देरी बर्बर नहीं की जाएगी।

यह फैसला न केवल प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा करने वाला है, बल्कि स्थानीय शासन की स्वायत्तता को लेकर एक बड़ा संदेश भी है। न्यायालय ने लगातार तीन दिनों तक चली सघन दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित नहीं रखा, बल्कि सरकार को कड़े निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया 30 अप्रैल से पहले संपन्न करा ली।

बिरादरी की बातें

चूहा- सुनती हो, महाराष्ट्र अंबरनाथ नगर पालिका परिषद के 12 कांग्रेसी पाषंड भाजपा में शामिल हो गए।
चुटिया- हां जी, लोग नाहक ही हल्ला कर रहे थे कि कांग्रेस-भाजपा का गठबंधन हो गया।

छत्तीसगढ़ में शिक्षक प्रमोशन पर हाईकोर्ट की सख्ती; पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक

रायपुर, 9 जनवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग में चल रही पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्राथमिक शाला के हेड मास्टर से लेकर पद पर पदोन्नति से संबंधित मामलों में अंतिम आदेश जारी करते हुए 22 दिसंबर 2025 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। याचिकाकर्ता बुद्धेश मिश्रा एवं अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया कि वे वर्ष 2010 से हेड मास्टर प्राथमिक के पद पर कार्यरत हैं। 1 जनवरी 2022 को आयोजित डीपीसी में उन्हें पदोन्नति के लिए योग्य भी घोषित किया गया था, लेकिन कुछ याचिकाओं के लॉबिंग रहने के कारण उस समय पदोन्नति आदेश जारी नहीं हो सका। याचिका में बताया गया



कि संबंधित प्रकरणों का 9 मार्च 2023 को अंतिम निष्कर्ष हो गया था, जिसके बाद पदोन्नति में कोई कानूनी अड़चन शेष नहीं रहा। इसके बावजूद शिक्षा विभाग ने 2022 की डीपीसी को लागू नहीं किया, जो याचिकाकर्ताओं के साथ अन्याय है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि कोर्ट में मामला लंबित रहते हुए वरिष्ठ सूची की

अंतिम रूप दिए बिना नया नियम लागू कर दिया गया, जो नियमों के खिलाफ है। याचिका में यह भी कहा गया कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक व प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती एवं पदोन्नति नियम 2019 का उल्लंघन करते हुए 22 दिसंबर 2025 को नया नियम लागू किया गया, जिसमें केवल शिक्षक एलबी संवर्ग को शामिल किया गया। ई संवर्ग के नियमों शिक्षकों को पूरी तरह बाहर कर दिया गया, जो नियमों और समानता के सिद्धांत के विपरीत है। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने पदोन्नति प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अन्य इस प्रकरण में आगे की सुनवाई के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी।

बंगाल में ईडी की कार्रवाई का दिल्ली तक विरोध, महुआ मोइजा समेत कई सांसद सड़कों पर; सरकार को घेरा

नई दिल्ली, 9 जनवरी (न्यूज चैनल)। टीएमपीसी ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां चुनाव से पहले पार्टी के रणनीतिक दस्तावेजों तथा डेटा को छाप लगाने की कोशिश कर रही हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और गरमाया गया है। पार्टी का कहना है कि यह कार्रवाई चुनाव वर्ष में राजनीति का दबाव पैदा करने की याचिका का हिस्सा है। दिल्ली समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसमें टीएमपीसी नेताओं ने प्रवर्तन निदेशालय को आई पीएसों के खिलाफ छापमारी का विरोध करते हुए केंद्र सरकार पर कड़ी टिप्पणियां कीं।



तुमपुल कोसिम (टीएमपीसी) ने आई-पैक पर ईडी की छापमारी के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। टीएमपीसी की याचिका में कहा गया है कि पार्टी पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जिसके चलते ईडी ने पार्टी के राजनीतिक रणनीति कार्यालय और इसके सह-संस्थापक के निवास पर छापमारी की। याचिका में यह भी कहा गया है कि गोपनीय डेटा और दस्तावेजों को अवैध रूप से जब्त किया गया, जो कानून के खिलाफ है। टीएमपीसी ने अदालत से ईडी की कार्रवाई को रोकने और अवैध दस्तावेज जवाब को रद्द करने की मांग की है।

एसआईआर के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थी, जिसके चलते ईडी ने पार्टी के राजनीतिक रणनीति कार्यालय और इसके सह-संस्थापक के निवास पर छापमारी की। याचिका में यह भी कहा गया है कि गोपनीय डेटा और दस्तावेजों को अवैध रूप से जब्त किया गया, जो कानून के खिलाफ है। टीएमपीसी ने अदालत से ईडी की कार्रवाई को रोकने और अवैध दस्तावेज जवाब को रद्द करने की मांग की है।

ट्रेक्टर से गिरकर मासूम की मौत, मामला दबावे झूठे शव के गड्ढे में दफनाया शव

राजनंदगांव, 9 जनवरी (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव जिले के झुंझिया थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। ग्राम निवासे प्रताप मीसासु प्रभात अग्रवाल की मौत ट्रेक्टर से गिरने से हो गई, जिसके बाद आरोपी ट्रेक्टर चालक ने मामले को छिपाने के लिए शव को खाद के गड्ढे में दबा दिया। मासूम बच्चे के पिता ने अपने पुत्र की गुप्त दफनाई की जानकारी संबंधित झुंझिया थाने में दी थी। पुलिस को पड़ताल में पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने शव बरामद कर लिया है और मामले में जांच की विधि समेत कार्रवाई जारी है।



मिली जानकारी के अनुसार, प्रभात अग्रवाल ट्रेक्टर में बैठा हुआ था। इसी दौरान वह अचानक ट्रेक्टर से गिर पड़ा और पहाड़ की चोटी पर आ गया, जिससे उसकी मौत पर हो गई। हादसे के बाद ट्रेक्टर चालक ने घटना की जानकारी

परिजनों को देने के बजाय मामले को दबावे के लिए शव को खाद के गड्ढे में दफना दिया था। घटना के बाद मासूम के पिता ने अपने पुत्र के गुमसुत होने की शिकायत संबंधित थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस को जांच-पड़ताल के दौरान पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने आरोपी को निशानदेही पर खाद गड्ढे से मासूम का शव बरामद कर मौजूद है और आरोपी ट्रेक्टर चालक से पड़ताल की जा रही है। मामले में हत्या, सड़त छिपाने समेत अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

मुझे हटाए बिना अध्यक्ष की घोषणा वैधानिक नहीं: बृजमोहन

रायपुर, 9 जनवरी (हाईवे चैनल)। राष्ट्रीय रेवर-रेंजर जंबूरी को लेकर गरमाई सियासत पर सांसद बृजमोहन आग्रवाल ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली प्रवास से देर रात रायपुर लौटते के बाद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि परिपद में वैधानिक प्रक्रिया को अनदेखी की गई। वैधानिक अध्यक्ष होने के बावजूद उन्हें हटाए बिना नए अध्यक्ष की घोषणा करना नियमों के खिलाफ है, जिसके चलते उन्होंने न्यायालय का रुख किया है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली दौरे और अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया।



सांसद बृजमोहन आग्रवाल ने बताया कि दिल्ली प्रवास के दौरान केमिस्टल फॉरेंसिकलर की बैठक थी। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि देशभर के किसानों को किस तरह से सस्ती खाद उपलब्ध करा सकते हैं। इसी बैठक जैसी की बुलाई गई थी, जिसमें 1/30 अर्सेजेंट बिल है। इसमें कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री आए 30 दिनों के लिए तैयार किया जाता है, तो उसका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। तीसरी बैठक एग्जिस्टेंट कमेटी की थी, जिसमें

स्कूल शिक्षा और समग्र शिक्षा को नगोदय विद्यालयों को देने के लिए चर्चा की गई थी। राष्ट्रीय रेवरड्यूरेजर जंबूरी को लेकर गरमाई सियासत और रायपुर लौटते के बाद एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि परिपद में वैधानिक प्रक्रिया को अनदेखी की गई। वैधानिक अध्यक्ष होने के बावजूद उन्हें हटाए बिना नए अध्यक्ष की घोषणा करना नियमों के खिलाफ है, जिसके चलते उन्होंने न्यायालय का रुख किया है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली दौरे और अन्य मुद्दों पर भी बयान दिया।

सांसद ने जंबूरी परिपद विवाद पर दिया बड़ा बयान

कि अध्यक्ष पद पांच साल के लिए होता है और अगर कुछे हटाए बिना अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, तो मैं कोर्ट जाऊंगा। उन्होंने बताया कि मैं कोर्ट गया हूँ। मुझे हटाए बिना अध्यक्ष को जो घोषणा सरकार ने की है, वह वैधानिक नहीं है। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम टीएम सिंह ने बैठक जैसी की बुलाई गई थी, जिसमें 1/30 अर्सेजेंट बिल है। इसमें कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मंत्री आए 30 दिनों के लिए तैयार किया जाता है, तो उसका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा। तीसरी बैठक एग्जिस्टेंट कमेटी की थी, जिसमें

छज्जा गिरने से छात्र की मौत, प्रधान पाठक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई

बलरामपुर, 9 जनवरी (हाईवे चैनल)। वाङ्गनगर थाना क्षेत्र के शारदापुर गांव में निर्माणधीन आंगनवाड़ी भवन का छज्जा गिरने से गुस्त्रवा की 6वीं कक्षा के एक छात्र की मौत हो गई थी। इस दर्दनाक घटना को संयुक्त संचालक ने गंभीरतापूर्वक मानते हुए प्रमाण पाठक ममता गुप्ता पर निलंबन की कार्रवाई की है। वहीं शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। परिजनों ने मृतक के शव का अवतक संस्कार नहीं किया है। उनकी मांग की थी कि शिक्षकों, बिडिस्टा बचाने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए, हालांकि अब



3 शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस

शिक्षकों पर कार्रवाई के बाद मृतक का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। दरअसल, घटना शारदापुर गांव के खुदहन पारा स्थित माध्यमिक शाला की है, जहां अध्ययनरत छठवीं कक्षा का छात्र आलीक कुमार पिता रमेश देवान मध्यह

भोजन अवकाश के दौरान खेलते-खेलते स्कूल परिसर के पीछे निर्माणधीन भवन में पहुंच गया। इसी दौरान छज्जा गिरने से उसके नीचे आलीक दब गया। इसकी सूचना अन्य बच्चों द्वारा शिक्षकों पर पहुंची, जहां आलीक खूब से लथपथ मरने में दबा मिला। शिक्षकों और प्राध्यापकों की मदद से उसे बाहर निकालकर तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं परिजनों का रे-रेकर बुरा हाल है। पूरे घटनाक्रम में विद्यालय में शिक्षकों की लापरवाही सामने आई।